

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

RNI No :- DELHIN/2023/86499

DCP Licensing Number :

F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 02, अंक 297, नई दिल्ली। रविवार, 05 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 दिल्ली विधानसभा चुनावी दंगल में भाजपा की पहली टीम की घोषणा

06 मार्गदर्शन की आवश्यकता/क्षेत्र, सिद्धांत, परामर्श के उद्देश्य

08 महाकुंभ अर्थव्यवस्था, 45 दिन 90 हजार करोड़ जीडीपी

तीन मेट्रो लाइन, दो बस अड्डे और एक रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी से सफर होगा आसान

संजय बाटला

नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक यात्रा को आसान बनाएगी। यह दिल्ली मेट्रो की तीन लाइनों दो बस अड्डों और एक रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी जिससे विभिन्न शहरों की यात्रा सुलभ होगी। इससे लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों को आसान और सुलभ बनाएगी। इसे पीएम मोदी रविवार को हरी झंडी दिखाएंगे।

नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन केवल मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक का सफर ही आसान नहीं करेगी बल्कि तीन दिल्ली मेट्रो लाइन, दो बस अड्डे व एक रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी होने से विभिन्न शहरों का सफर भी आसान करेगी। इससे नमो भारत ट्रेन लाखों लोगों के सफर को आसान बनाएगी। यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों के सफर को आसान और सुलभ बनाएगी।

दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक संचालन होने से आनंद विहार स्टेशन पर नमो भारत की कनेक्टिविटी आनंद विहार

में दिल्ली मेट्रो ब्लू व पिंक लाइन से, आनंद विहार में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आइएसबीटी) का बस अड्डा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का कौशांबी बस अड्डा और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हो जाएगी।

विभिन्न राज्यों के शहरों के लोगों को राहत मिलेगी

इससे केवल दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ जाने का सफर ही आसान नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिविटी होने से बस अड्डों से संचालित हजारों बसों व रेलवे स्टेशन से जाने वाली रेल गाड़ियों से प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के शहरों के लोगों को राहत मिलेगी। जिन लोगों को यहां से दिल्ली या मेरठ जाना होगा व आसानी से आ जा सकेंगे। अभी तक बस में सफर कर कौशांबी व आनंद विहार पहुंचने वाले लोगों को विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी होती हैं।

मेट्रो रेड लाइन से पहले ही हो चुकी है कनेक्टिविटी

नमो भारत ट्रेन की दिल्ली मेट्रो रेड लाइन से शहीद स्थल स्टेशन पर पहले ही कनेक्टिविटी हो चुकी है। इससे भी तीनों



शहरों के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। अब पिंक व ब्लू लाइन के जुड़ने से लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी। लोगों का सफर सुगम बनेगा।

कौशांबी डिपो व आनंद विहार बस अड्डे से लाखों यात्री करते हैं सफर

कौशांबी व आनंद विहार बस अड्डे से आइएसबीटी व यूपीएसआरटीसी की रोडवेज बसों से रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। जो यहां विभिन्न कार्यों के लिए आते-जाते हैं। कौशांबी डिपो पर ही रोजाना 800 से 1000 बसों का डिपार्चर रहता है। इनसे करीब 40 हजार यात्री रोजाना सफर करते हैं।

दिल्ली मेट्रो की कौन-कौन सी लाइन जुड़ेगी

ब्लू लाइन: दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से वैशाली।

कुल स्टेशन 33
पिंक लाइन: लोनी शिव विहार से दिल्ली के मजलिस पार्क।

कुल स्टेशन 38
रेड लाइन: गाजियाबाद के शहीदनगर से दिल्ली के रिटाला।

कुल स्टेशन 29
ये रंगों नमो भारत ट्रेन के 11 स्टेशन

न्यू अशोक नगर
आनंद विहार
साहिबाबाद
गाजियाबाद

गुलधर
दुहाई
दुहाई डिपो स्टेशन
मुरादनगर

मांदिनगर साउथ
मांदिनगर नार्थ
मेरठ साउथ

दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ होना उत्तर प्रदेश व दिल्ली रहने वालों के लिए गर्व की बात है। इससे उद्यमी व नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से गाजियाबाद भी आते हैं। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। -इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)



रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सभी बसों में लगेंगे स्मार्ट डिवाइस



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी की घोषणा। सभी बसों में स्मार्ट डिवाइस लगाये जायेंगे। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये कदम उठाए जायेंगे। इस संबंध में आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह स्मार्ट डिवाइस तब सायरन बजाएगा जब चालक की आंखें बंद होंगी या वह आंखें खुली

रखते हुए भी ध्यान भटकाकर गाड़ी चला रहा होगा। एवम तक कि अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, तो भी एक ध्वनि सुनाई देगी जो चालक को सतक कर देगी। यह उपकरण सड़क समूहों को रोकने में भी मदद कर सकता है। सरकार आगामी बजट में इसकी व्यवस्था करेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओडिशा यात्री ऐप का उद्घाटन किया। इससे यात्रियों को एक बिलक पर अपने गंतव्य तक ऑटो और

टैक्सी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,000 यातायात पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। ओला, उबर ये सभी वाणिज्यिक आधार पर चल रही हैं। इससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है। कंपनी ड्राइवर्स से कमीशन ले रही है। यह ऐप राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है ताकि इन सब चीजों को खत्म किया जा सके और स्वच्छता लाई जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस पर ओडिशा यात्री ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।

पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद में होंगे, कई रास्ते बंद, पुलिस ने एडवाइजरी की जारी; घर से निकलने से पहले देखें रूट

प्रधानमंत्री के साहिबाबाद आगमन के मद्देनजर रविवार सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त तक यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। मोहननगर से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार तक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार से वैशाली मेट्रो के मध्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घर से निकलने से पहले देखें रूट।

साहिबाबाद। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व रविवार को सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। यदि आप घर से निकल रहे हैं तो रूट देखकर निकलें। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार से यूपी गेट तक वाया मोहननगर-वसुंधरा-वैशाली रूट सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्त तक प्रभावित रहेगा।

एसा होगा रूट डायवर्जन
मोहननगर से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार के सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मोहननगर से यूपी गेट के मध्य सभी भारी/मध्यम/हल्के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। करन गेट गोलचक्कर से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार की ओर सभी प्रकार के



ट्रैफिक डायवर्जन लागू

व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

रोटरी गोलचक्कर से नागद्वार होकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार की जाने वाले सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन प्रवेश द्वार से वैशाली मेट्रो (वाया मोहननगर) के मध्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

समस्या आने पर इन नंबरों पर करें कॉल
यातायात हेल्पलाइन नंबर : 9643322904, 0120-2006100
यातायात निरीक्षक, मुख्यालय, संतोष

सिंह चौहान, मो.नंबर: 7007847097
यातायात निरीक्षक, चतुर्थ, मनोज कुमार

मो.नंबर: 8130674912
यातायात निरीक्षक, पंचम, अजय कुमार,

मो.नंबर: 9210005151
यह डायवर्जन पीएम मोदी का कार्यक्रम समाप्त होने तक रहेगा लागू

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यह डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। नागद्वार से हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर के बीच भी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। प्रधानमंत्री के साहिबाबाद में आगमन के दौरान हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर से वैशाली मेट्रो स्टेशन के बीच सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कानून-व्यवस्था के लिए बीएसएफ की धारा 163 लागू की है। पुलिस से कोतवाली, मधुबन बापूधाम, नंदग्राम, लिंक रोड, साहिबाबाद, इंद्रपुरम, सिहानी गेट और कौशांबी थानाक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। इन आठ थानाक्षेत्रों को नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन घोषित किया गया है।

बता दें इससे पहले शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के रविवार को नमो भारत स्टेशन साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर दिल्ली जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री के तय रूट व नमो भारत स्टेशन को स्वागत के लिए सजाया जा रहा है।

250 किमी निर्माणाधीन मेट्रो लाइन, "आप" सरकार का दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर

सुषमा रानी

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में "आप" सरकार दिल्ली के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर गंभीर है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बताया कि रविवार को केंद्र सरकार और दिल्ली की रीआप सरकार मिलकर दिल्ली-एनसीआर को नई मेट्रो लाइन और आरआरटीएस की सौगात देने जा रही है। रविवार को दिल्ली मेट्रो फेज-4 के रिटाला-कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास और जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। जबकि न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच आरआरटीएस लाइन का उद्घाटन होगा। वहीं, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में रीआप की सरकार में 200 किमी मेट्रो लाइन बनीं और 250 किमी से ज्यादा मेट्रो लाइन निर्माणाधीन है। 2015 से अबतक हमने मेट्रो विस्तार के लिए 7,278 करोड़ रुपए निवेश किया है, जबकि आरआरटीएस में 1,260 करोड़

रुपए दिए हैं। सीएम आतिशी ने कहा कि रविवार को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक अहम दिन है। क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं, उन दो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होने वाला है। रविवार को दिल्ली मेट्रो की रिटाला से कुंडली कॉरिडोर, जो फेज 4 में आता है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं मेट्रो की मजेटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से कृष्णापुरी पार्क तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। रविवार से वह मेट्रो लाइन काम करना शुरू कर देगी। सीएम आतिशी ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में मजेटा लाइन भी बनी, जिसमें बॉटैनिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर और कालकाजी मंदिर से जनकपुरी वेस्ट को जोड़ा गया। ग्रेलाइन बनी, जहां हाल ही में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के विस्तार में द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो का विस्तार हुआ है।



सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का जितना विस्तार पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ, उतना विस्तार पहले कभी नहीं हुआ। जब मेट्रो की रफ्तार बढ़ती है, लोगों की आवाजाही की रफ्तार बढ़ती है, तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। यही कारण है कि दिल्ली का जीएसडीपी लगातार बढ़ रहा है और यहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है।

सीएम आतिशी ने कहा कि रविवार को इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) का भी उद्घाटन है। एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन), जिसका कुंभ हिस्सा यूपी, हरियाणा और राजस्थान

है। यह एनसीआर दिल्ली के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोनीपत, बल्लभगढ़, नोएडा या फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन दिल्ली आकर काम करते हैं। वैसे ही दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो रहते दिल्ली में हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए गुरुग्राम, नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाते हैं। इसलिए इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की राज्य सरकारों ने मिलकर फंड किया है। दिल्ली सरकार ने इस आरआरटीएस में 1,260 करोड़ रुपए दिए हैं। आरआरटीएस में अभी तीन कॉरिडोर को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली-अलवर

कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर शामिल हैं। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का एमओयू साइन हो चुका है। हमारी सरकार ने इसके लिए 1,260 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। वहीं, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई उन्होंने कहा कि आरआरटीएस जो केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। रविवार को आरआरटीएस के पहले हिस्से का उद्घाटन होगा। इसमें पहली लाइन साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक इस आरआरटीएस लाइन की शुरुआत की जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस दोनों प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि रविवार को केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर दिल्ली मेट्रो की नई लाइन और आरआरटीएस की नई लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं।

महाकुंभ "अर्थव्यवस्था", 45 दिन 90 हजार करोड़ जीडीपी



संजय बाटला

अब जाकर समझ आया और अब आप भी समझे सनातन सिर्फ धर्म नहीं स्वयं में ही अर्थव्यवस्था है। अयोध्या, काशी जैसे धार्मिक स्थल और कुम्भ जैसे लगने वाले धार्मिक उत्सव भारत देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं। जो लोग यह कहते हैं कि क्या मंदिर खाना देगा तो आज दुनिया देख रही है कि सनातन का यह हिस्सा ही है अर्थव्यवस्था के चक्र को तेजी से घुमा रहा है।

10 बिलियन डॉलर यानि 90 हजार

करोड़ रुपया कुम्भ से,

अंदाजान 45 करोड़ लोग कुम्भ में आएंगे और अगर औसत हर इंसान का खर्चा मात्र 2000 रुपए मान लिया जाए तो आप हुए लोग खर्च करते हैं 90000 करोड़ यानि 10 बिलियन डॉलर। अर्थात सिर्फ एक कुम्भ मेले से 90000 करोड़ से ज्यादा की जीडीपी पैदा होगी और वह भी मात्र एक उत्सव और एक शहर से। जब की दुनिया देख रही है कि सनातन आज भी 7 बिलियन के कर्ज के लिए आईएमएफ के पीछे लगा है।

स्कूलों में छात्रों की संख्या का घटना चिन्ताजनक

ललित गर्ग

भारत में शिक्षा प्रणाली लाखों छात्रों के जीवन और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ, भारत में एक जटिल और विशाल शैक्षिक परिदृश्य है।

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, पर स्कूली छात्रों की संख्या घट रही है। स्कूली छात्रों की संख्या घटना न केवल चिन्ताजनक और विचारणीय है बल्कि नये भारत-सशक्त भारत निर्माण की एक बड़ी बाधा भी है। भारत में स्कूलों की संख्या में करीब 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों सहित 14,89,115 स्कूल हैं। ये स्कूल 26,52,35,830 छात्रों को पढ़ाते हैं। इनमें से कुछ स्कूलों को उनकी प्रतिष्ठा, स्थापना के वर्षों, महत्वपूर्ण स्कूल परिणामों, मार्केटिंग रणनीतियों आदि के कारण उच्च छात्र नामांकन प्राप्त होते हैं लेकिन पर साल 2022-23 व 2023-24 के बीच स्कूली छात्रों के नामांकन में 37 लाख की कमी आई है। यह स्थिति अनेक सवाल खड़े करती है। क्या स्कूली शिक्षा ज्यादातर बच्चों की पहुंच के बाहर है? क्या शिक्षा का आकर्षण पहले की तुलना में घटा है?

भारत में शिक्षा प्रणाली लाखों छात्रों के जीवन और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति के साथ, भारत में एक जटिल और विशाल शैक्षिक परिदृश्य है। भारत में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न चरण शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। डेटा एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की यह ताजा रिपोर्ट देश के स्कूली इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के साथ ही उन अहम दिक्कतों की भी झलक देती है, जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर होने के बावजूद छात्रों की संख्या का घटना गहन विमर्श का विषय है।

शिक्षा मानव-जीवन के विकास का आधार स्तंभ है। शिक्षा के अभाव में मानव-जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह मनुष्य को उत्कृष्टता एवं उच्चता के शिखर पर स्थापित करती है। शिक्षा प्रकाश एवं शक्ति का ऐसा स्रोत है जो नये भारत के विकास का आधार है। जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ तथा क्षमताओं का निरन्तर सामंजस्यपूर्ण विकास करके नये भारत, सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती देता है। देश में पिछले साल के मुकाबले स्कूलों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन छात्रों के नामांकन में गिरावट देखी गई है। जहां स्कूलों की संख्या 14.66 लाख से बढ़कर 14.71 लाख हो गई वहीं इनमें होने वाला छात्रों का नामांकन 25.17 करोड़ से घटकर 24.80 करोड़ हो गया। यह गिरावट कर्मोबेश सभी श्रेणियों यानी लड़के लड़कियाँ, ओबीसी, अल्पसंख्यक आदि में है। जहां तक शिक्षा के बीच में छात्रों के स्कूल छोड़ने के मामलों की बात है तो इसमें सेकेंडरी स्तर में होने वाली बढ़ोतरी ज्यादा परेशान करने वाली है। मिडल



स्कूलों में जो डॉपआउट दर 5.2 प्रतिशत है, वह सेकेंडरी स्टेज में आकर 10.9 प्रतिशत हो जाती है। इसके पीछे ओबीसी और एससी-एसटी श्रेणी के छात्रों को दाखिले के दौरान होने वाली जटिल प्रक्रिया, मुश्किलें और किसी अभावग्रस्त छात्र के लिए आर्थिक मदद या छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं की कमी का हाथ हो सकता है। छात्रों के नामांकन की घटती संख्या को जाति के आधार पर अगर देखें, तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के नामांकन में 25 लाख से अधिक, अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के छात्रों में 12 लाख और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के छात्रों में दो लाख की

गिरावट हुई है। नामांकन से वंचित हुए अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या तीन लाख है, जबकि इनमें से एक तिहाई मुस्लिम हैं। भारत में नई पीढ़ी को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा से वंचित रहने के जो कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण गरीबी है। सरकारी स्तर पर सरकारों ने गरीब छात्रों के लिए अनेक इंतजाम किए हैं, पर इन इंतजामों का सभी छात्रों तक समान रूप से पहुंचना आसान नहीं है। निचले स्तर पर शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों को जितना सजग होना चाहिए, उतना सजग वे नहीं हो पा रहे हैं। भारत जैसे देश में शिक्षा एक अभियान है, इसके लिए अगर नियोजित एवं

उत्साहपूर्ण माहौल न बनाया जाए, तो गरीब व वंचित बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। कोई संदेह नहीं कि किसी भी अभियान में अगर समर्पित लोग आपके पास नहीं हैं, तो फिर उस अभियान की सफलता संदिग्ध हो जाती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। यदि हमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है तो कई पहलुओं एवं मोर्चों पर काम करना आवश्यक है। हमारी आजादी के बाद से ही शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने हमें दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनने से रोक

दिया है। भारत में एक सभ्य शिक्षा प्रणाली के महत्व की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नयी शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। देश की शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया जा रहा है और शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। प्रणाली को आधुनिक बनाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने के प्रयास हो रहे हैं। बहरहाल, यह खुशी की बात है कि अब भारत के 91.7 प्रतिशत स्कूलों तक बिजली पहुंच चुकी है। अभियान चलाकर देश के बाकी बचे स्कूलों तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। देश में 98 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों तक पेयजल सुविधा के साथ ही टॉयलेट की सुविधा पहुंच चुकी है। स्कूलों को संसाधन संपन्न बनाने के साथ ही शिक्षकों और पुस्तकों की गुणवत्ता एवं स्कूलों को संसाधन के स्तर पर भी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। भारत के 60 प्रतिशत स्कूलों में भी कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं और इंटरनेट की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है। आज के समय में जब हमें बड़े पैमाने पर कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी, तब किसी का कंप्यूटर शिक्षा से वंचित होना बहुत महंगा पड़ेगा। आज के समय में हर छात्र या हर नागरिक को कंप्यूटर और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। कंप्यूटर आज के समय में कौशल विकास का आधार है। हालांकि, कई स्कूल अभिभावकों और छात्रों को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इन संघर्ष की स्थितियों का निर्यात होना जरूरी है। इसी से

भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था एवं विश्व गुरु होने का दर्जा पा सकेगा। क्योंकि शिक्षा दृष्टि और दृष्टिकोण को बढ़ाती है, जिससे समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। इससे उन्नत एवं चरित्रसम्पन्न नागरिकों का निर्माण होता है एवं देश विकास की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति करने की इच्छा भी बढ़ती है, अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, असमानता और सांप्रदायिकता आदि से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षा एक ऐसे लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है जिसमें एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज शामिल हो। यह आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान में भी मदद करता है और कई नौकरी और रोजगार के अवसरों का निर्माण सुनिश्चित करता है। एक सभ्य शिक्षा प्रणाली विचारों, ज्ञान और अच्छी प्रथाओं का शांतिपूर्ण आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है। यह अपराध और आतंकवाद को कम करने में मदद करता है; इस प्रकार, कानून और व्यवस्था के मुद्दों को नियंत्रण में रखा जाता है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने के साथ-साथ भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करती है। भारतीय परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। उचित बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षा के प्रति समाज के कई वर्गों में कम उत्साह के कारण भारत में शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतियाँ हैं जिनके कारण भारत इष्टतम विकास को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बेहतर बनाने एवं छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए उभ नीतियों पर सख्ती से काम करने की आवश्यकता है जो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करें।

शिक्षा का गिरता स्तर: चिन्ता का विषय

वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और चिन्ता का विषय है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा सभी प्रकार के किले फोटे किए जा सकते हैं और देश तरक्की कर सकता है, परंतु चिन्ता का विषय है कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। एक समय था जब कक्षा चार पांच तक पढ़ा व्यक्ति अच्छे-अच्छे पदों पर काम करता था, परंतु आजकल का बीए पढ़ा विद्यार्थी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी वजह हमारी शिक्षा का गिरता स्तर व उस में पाई जाने वाली बहुत सी खामियाँ हैं।

सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रकार की मुफ्त सुविधाएँ होते हुए भी माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, इसकी वजह यह है कि प्राथमिक स्कूल ही बच्चे का आधार होता है वहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्राथमिक स्कूलों में एक तो अध्यापकों की कमी रहती है एक या दो अध्यापकों के सहारे ही स्कूल चलाए जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त जो दूसरे कार्य हैं डाक बनाना, हिसाब-किताब रखना जैसे बहुत से कार्य होते हैं जो पढ़ाई में बाधक हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाए या इन कार्यों का हिसाब-किताब करें। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं। पहले ही स्टाफ की कमी ऊपर से दूसरे कामों का बोझ। अभी अध्यापक स्कूल की पूरी व्यवस्था और

बच्चों को समझ नहीं पाता कि कमी कहाँ है? थोड़ा बहुत प्रयास करता है सुधारने के लिए कि उसे बदली का डर सनाने लगता है। नया अध्यापक बच्चों को समझने में समय लगा देता है, परंतु उसका पढ़ाने का अपना तरीका होता है। बच्चे उस तरीके को अच्छी तरह से नहीं अपना पाते शिक्षा का स्तर गिरता है। बहुत से माता-पिता ऐसे हैं जो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते। स्कूल में अध्यापकों के बुलाने पर भी बहुत कम आते हैं। पहली से आठवीं तक देखे प्रेडिग सिस्टम बिलकुल सही नहीं है। अध्यापक मेहनत तो करवाते हैं परंतु बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको पता है कि हम तो बिना पढ़े, बिना कुछ लिखे भी पास ही हैं। बच्चे आठवीं पास कर जाते हैं, परंतु सरकार की अच्छी पहल है कि अब पांचवीं और आठवीं में भी बच्चे फेल होंगे। माता-पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनके बच्चे को कुछ आएँ चाहे न आएँ। उनको तो बस इतना है कि बच्चा पास हो गया नौवीं कक्षा में पहुँच गया। बच्चा ठीक ही चल रहा है। माध्यमिक स्कूलों से बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो लिखने पढ़ने में काफी कमजोर होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे भी आते हैं। नौवीं कक्षा में वे बच्चे अच्छे बच्चों के साथ नहीं चल पाते और उनकी कमियाँ वैसे की वैसे बनी रहती हैं। शिक्षा के स्तर का गिरना कोरोना महामारी की भी वजह है। उस दौरान पढ़ाई में जो कमी रह गई उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है। नौवीं-दसवीं कक्षा में बच्चे थोड़े समझदार तो हो जाते हैं। अपना अच्छा बुरा समझने लग जाते हैं, परंतु बाहर



का वातावरण उनको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। बच्चे फोन का सही इस्तेमाल न करके उसका दुरुपयोग करते हैं। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। कमियाँ उनकी जैसी की तैसी बनी रहती हैं। दूसरे बच्चे यह सोचते हैं कि पढ़ने का क्या फायदा कोई नौकरी तो मिलनी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छठी से बारहवीं तक रोजगार परक शिक्षा को लेकर आई है जो कि एक अच्छी पहल है। हमें उसे धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा न हो कि उसकी सिद्धांतिक जानकारी दी जाए, परंतु व्यावहारिक ज्ञान से उसे जोड़ा न जाए। हमें उससे भी उसे जोड़ना होगा। हमारे सीमावर्ती बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहाँ या तो अध्यापक टिक नहीं पाते हैं यदि टिक पाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें वहाँ आती हैं। जिस कक्षा में 100 विद्यार्थी होंगे अध्यापक क्या-क्या करेगा। पढ़ाई करवाएगा या दूसरे काम निपटाएगा। अगर एक ही अध्यापक वहाँ से चला जाता है, दूसरा वहाँ आसानी से नहीं

आ पाता। एक ही अध्यापक की बात नहीं दो-दो, तीन-तीन पद खाली रहते हैं। सारा बोझ दूसरे अध्यापकों पर पड़ जाता है। अगर कोई अध्यापक वहाँ पर आता है तो विवशता के कारण जिसको कहीं जगह नहीं मिलती। दूसरे आजकल किसी बच्चे को कोई कुछ कह भी नहीं सकता। जब बच्चे को सही व्यवस्था नहीं मिलेगी तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सही पढ़ाई नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा। शिक्षा का स्तर गिरने की एक वजह यह भी है कि जो अच्छे-अच्छे बच्चे होते हैं निजी स्कूलों में चले जाते हैं। जिन बच्चों के माता-पिता निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते वे बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले लेते हैं। जो बच्चे निजी स्कूलों में नहीं चल पाते हैं उनके माता-पिता भी उनको सरकारी स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे जितने कार्य होते हैं उतने शायद निजी स्कूलों में नहीं होते। चुनावों की चिन्ता उनको नहीं है। वोट बनाना, छात्रवृत्ति का कार्य, दोपहर

का भोजन, जनगणना, अन्य गतिविधियाँ, उनकी तैयारी करवाना, फोटो खींचना, अपलोड करना, जिस कार्य में प्रभाती हैं उसकी सारी जिम्मेदारी निभाना। जबकि निजी स्कूलों में अध्यापकों का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही होता है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी पांच दिन की ट्रेनिंग, कभी दस दिन की ट्रेनिंग शिक्षा का स्तर तो गिरेगा ही। और भी बहुत सी खामियाँ हैं जिनके कारण शिक्षा के स्तर व बच्चों की संख्या में कमी होती जा रही है। जिसकी वजह उचित सुविधाओं का न होना भी है। पैदल चलने का इंतजाम भी बच्चों की घटती संख्या का कारण है। आज के जमाने में कोई भी ऐसे अभिभावक नहीं होंगे जो अपने बच्चों को वर्दी, खाना, किताबें आदि सुहैया नहीं करवा सकते। उन्हें मुफ्त सुविधाओं की बजाय अच्छी शिक्षा चाहिए। जो उनके बच्चे को प्रतियोगिता के जमाने में कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाएँ। शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए जरूरी है शिक्षा स्तर में पाई जाने वाली कमियों को दूर करना। अधिक से अधिक बजट का प्रावधान और उसका सदुपयोग करना। कमरों की, अध्यापकों की कमी को दूर करना। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना जो शिक्षा स्तर के गिरावट का कारण है। सरकारी स्कूलों में वे सभी सुविधाएँ देना जो निजी स्कूलों में उपलब्ध है। अध्यापकों के ऊपर जो अन्यायपूर्ण बोझ डाला जा रहा है उसे कम करना। अध्यापकों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए गुणवत्ता से युक्त शिक्षा देना। डा. जयपाल ठाकुर शिक्षाविद

सांप को दूध पिलाने जैसी है इन 5 लोगों से दोस्ती

एक कहावत है सांप को दूध पिलाना यानी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना जो आपका बुरा ही चाहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोस्ती (Toxic Friendship) आपके जीवन में तूफान ला सकती है। ये लोग आपके साथ छल-कपट करते हैं आपका फायदा उठाते हैं और आखिर में आपको बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। आइए यहां आपको ऐसे ही 5 दोस्तों (Fake Friends) के बारे में बताते हैं।



हैं। वे आपके सामने बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुराई करते हैं। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं और आपको धोखा देते हैं।

रखते हैं जलन
ये लोग हमेशा दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। वे आपको खुशी नहीं देख सकते और आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये लोग सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी से ज्यादा और कुछ नहीं लाते हैं।
सेल्फ ऑब्सेस्ड
ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी मदद करें लेकिन जब आप उनकी मदद की जरूरत में होते हैं तो वे आपको अकेला छोड़ देते हैं।
झूठे लोग
ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग आपको धोखा देने में माहिर होते हैं। ये लोग आपके साथ विश्वासघात

करते हैं और आपके रिश्तों को भी बर्बाद कर देते हैं।
आलसी लोग
मेहनत से दूर रहना ऐसे लोगों का आदत होती है। ये लोग हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे उनके लिए काम करें। यकीन मानिए, ऐसे दोस्त आपके जिंदगी में एक बोझ की तरह होते हैं।
बेहद नुकसानदायक है इन लोगों से दोस्ती
इन लोगों के साथ रहने से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो सकते हैं।
ऐसे लोगों से धोखा खाने के बाद आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे।
जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो अपने अंदर की आवाज सुनें। अगर आपको कुछ अजीब लगता है तो उस व्यक्ति से दूरी बना लें।
हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट और मेहनती लोगों के साथ दोस्ती करें।
खुद पर विश्वास रखें और अपने गोल्ले को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या के नाते यूपी सर्वाधिक लाभान्वित राज्य

अयोध्या तो इसका उदाहरण मात्र है। पर्यटकों की पसंद की अन्य जगहों पर भी कमोबेश यही स्थिति है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी बूम पर है। हॉस्पिटैलिटी और इससे जुड़े सेक्टर में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के नाते स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है। ग्लोबल हार्बरिंग इनडूटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रिकवरी में 50 फीसद की वृद्धि देखी गई। अगले कुछ वर्षों तक इसमें 24 फीसद तक की और वृद्धि संभव है। इसका स्वाभाविक लाभ अयोध्या, वाराणसी, ब्रज और जेवर आदि और इनके आसपास के शहरों को मिलेगा। मसलन, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद से ही अयोध्या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का पसंदीदा स्थल बन कर उभरा है। कई नामचीन ब्रांड वहाँ होटल बनाने को लालायित हैं। ताज सहित दो दर्जन से अधिक होटलों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। स्थानीय होटल भी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी के विस्तार और बेहतरी में लगे हैं। अयोध्या तो इसका उदाहरण मात्र है। पर्यटकों की पसंद की अन्य जगहों पर भी कमोबेश यही स्थिति है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पसंदीदा स्थल के



रूप में उभरा है।
सीएम योगी की मंशा पर्यटन को जन उद्योग बनाने की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा तो पर्यटन को स्थानीय लोगों से जोड़कर इसे जन उद्योग बनाने की है। इसीलिए वह प्रयागराज के महाकुंभ और मकर संक्राति से लेकर करीब महीने भर तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में चलने वाले खिचड़ी मेले तथा ऐसे ही अन्य अवसरों के लिए कह चुके हैं कि स्थानीय लोग पर्यटकों, श्रद्धालुओं की सेवा सत्कार से इसे ब्रांड बनाएँ। सरकार अपनी ओर से इस बाबत जो संभव है, वह कर रही है।
इंडस्ट्री के लिए कुछ और छूट देने का विचार कर रही सरकार
प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के

सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी सहित प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में होटल के निर्माण में कुछ और छूट देने की भी सोच रही है। जगह के मानकों को लेकर कुछ छूट दी भी गई है। होम स्टे को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
क्या कहते हैं इंडस्ट्री के लोग
आईटीसी मौर्या नई दिल्ली में वैक्वेट मैनेजर रहे भव्य मल्होत्रा के मुताबिक प्रति कम्पन, तीन सर्विस प्रोवाइडर किसी अच्छे होटल के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसमें फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज, लाउंड्री, फाइनेंस, एचआर, हॉटिकल्चर, सेल्स आदि विभाग होते हैं। अगर प्रॉपर्टी छोटी है तो कुछ विभाग न होने से सर्विस प्रोवाइडर्स को संख्या कुछ कम हो

सकती है। पर, प्रति कम्पन दो कर्मचारी तो होने ही चाहिए। इससे काम होने पर आप अपने प्राहकों को संतोषजनक सेवा नहीं दे पाएंगे।
हॉस्पिटैलिटी के साथ इससे जुड़े सेक्टर की भी चांदी
पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का लाभ होटल इंडस्ट्री के अलावा इससे जुड़े एविएशन, रेलवे, सड़क परिवहन निगम और लाजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर और स्थानीय लोगों को भी होगा। वहाँ के खास उत्पाद की खरीद होने पर स्थानीय कला या उत्पाद को पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजना ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) की अपने आप ब्रांडिंग हो जाएगी।

साल 2025 में बंद हुई बजाज की 3 मोटरसाइकिल, लिस्ट में पल्सर F250 और प्लेटिना 110 ABS शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

नए साल की शुरुआत के साथ ही ऑटोमेकर बजाज ने अपनी मोटरसाइकिलों को भारतीय बाजार के लिए बिक्री को बंद कर दिया है। यह बाइक पल्सर F250 CT 125X और प्लेटिना 110 ABS है। इन मोटरसाइकिलों को बंद करने के पीछे की वजह इनकी बिक्री नहीं होना बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि बजाज ऑटो की यह तीनों बाइक किन फीचर्स के साथ आती थी।

नई दिल्ली। बजाज ऑटो ने जनवरी 2025 में अपनी मोटरसाइकिल को भारत में बंद करने का फैसला किया है। यह बाइक 110cc, 125cc और 250cc की है, जो पल्सर F250, CT 125X और

प्लेटिना 110 ABS है। इन बाइक को भारत में बंद करने को लेकर बजाज के लिए एक बड़ी रणनीतिक शिफ्ट को दिखाता है। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि इन बाइक की बिक्री और उत्पाद पोर्टफोलियो में बदलाव के संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन बाइक को क्यों बंद किया गया है।

बजाज ऑटो की डिस्कंटिन्यू बाइक Bajaj Pulsar F250

इसमें 249.07cc, एकल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 24.5 hp और 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें ट्रिपल-यूनिट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एलईडी हेडलाइट, और रियर टेललाइट



दिए गए थे। इसमें सस्पेंशन के रूप में टेलीस्कोपिक फ्रंट और मोनोशॉक रियर दिया गया था। इसमें

ABS और रियर डिस्क ब्रेक दिए गए थे। Bajaj CT 125X

यह एक कम्प्यूटर बाइक है, जो दमदार परफॉर्मेंस और किफायती कीमत के साथ आती थी। इसमें 124.4cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा हुआ इंजन 10.9 हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। बाइक के इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ से जोड़ा गया है। इसमें काले एलॉय व्हील्स, रियर टेल रैक और आरामदायक सीटें दी गई थीं। इसमें इयूल टॉन पेंट स्कीम और स्ट्राइलिश ग्राफिक्स दिए गए थे।

Bajaj Platina 110 ABS

यह कम्प्यूटर बाइक थी जो ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ आती थी। इसमें 115.45cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो 8.6 हॉर्सपावर और

9.81 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता था। बाइक के इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट और इयूल-स्रिंग रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए थे।

क्यों बंद हुई ये तीनों बाइक

बजाज की इन तीनों बाइक के बंद होने के पीछे का कारण उनकी बिक्री की कमी को माना जा रहा है। पल्सर F250, CT 125X, और प्लेटिना 110 ABS को लोगों ने हाथों-हाथ नहीं अपनाया जितना उन्होंने इसकी दूसरी बाइकों को अपनाया। इसके अलावा, ABS वरिएंट की कीमत भी इस सेगमेंट से बाकी मोटरसाइकिलों के मुकाबले ज्यादा थी, जिसकी वजह से बिक्री पर असर पड़ रहा था। जिसकी वजह से कंपनी ने इन बंद किया और अब वह अपने बाकी मॉडल्स पर ध्यान दे रही है।

नए रंगरूप में लॉन्च हुई Ather 450 सीरीज, मिले नए कलर ऑप्शन और फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

एथर एनर्जी ने Ather 450 सीरीज को नए साल 2025 के अवसर पर अपडेट किया है। इसे अपडेट करने के साथ ही कंपनी ने नए फीचर्स और नए कलर ऑप्शन भी दिए हैं। ऑटोमेकर ने Ather 450 सीरीज के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करने के साथ ही पूरे भारत में टेस्ट राइड और बुकिंग को भी शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी एथर एनर्जी ने Ather 450 सीरीज को अपडेट किया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को नए कलर और नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इसे लॉन्च करने के साथ ही इसकी पूरे भारत में टेस्ट राइड और बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं कि Ather 450 सीरीज के अपडेटेड मॉडल में क्या नए फीचर्स मिले हैं और इनकी कीमत कितनी है।

Ather 450 सीरीज की कीमत

Ather 450S की कीमत 1,29,999 रुपये।

Ather 450S Pro Pack की कीमत 1,43,999 रुपये।

Ather 450X 2.9kWh की कीमत 1,46,999 रुपये।

Ather 450X 2.9kWh Pro Pack की कीमत 1,63,999 रुपये।

Ather 450X 3.7kWh की कीमत 1,56,999 रुपये।

Ather 450X 3.7kWh Pro Pack



की कीमत 1,76,999 रुपये। Ather 450 Apex की कीमत 1,99,999 रुपये। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम, बंगलुरु की है।

Ather 450S

यह एथर 450 सीरीज का सबसे बेस वरिएंट है। इसमें 2.9kWh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने के बाद 122km तक की रेंज मिलेगी। इसमें बेसिक राइड मोड और कलर LCD स्क्रीन और मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, इसके प्रो पैक वरिएंट में नेविगेशन और एक्सट्रा राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसे कुल 4 कलर ऑप्शन में लाया गया है, जो स्टील व्हाइट, कॉस्मिक ब्लैक, स्पेस ग्रे और स्टील ब्लू है।

Ather 450X 2.9kWh

एथर के इस वरिएंट में 2.9kWh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने के बाद 126km तक का रेंज देगी। इसमें तेज एक्सलेरेशन और ज्यादा फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके प्रो पैक वरिएंट में म्यूजिक और कॉल के लिए ब्ल्यूथूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन के लिए Google मैप्स इंटीग्रेशन, ऑटोहोल्ड और फाईंड माई स्कूटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 450X में 450S के मौजूदा 4 कलर ऑप्शन के अलावा 3 और कलर में लाया गया है, जो लूनर ग्रे, टू रेड और हाइपर सैंड है।

Ather 450X 3.7kWh

एथर के 450X को 3.7kWh की बैटरी पैक के साथ भी लाया गया है। बैटरी पैक की

कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही इसकी रेंज को भी बढ़ाया गया है। यह फुल चार्ज होने के बाद 161 किलोमीटर तक का रेंज देगी। इसके प्रो पैक में बेहतर सस्पेंशन ट्यूनिंग और एडवांस्ड राइडिंग मोड समेत प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Ather 450 Apex

एथर का 450 एपेक्स वरिएंट इसका फ्लैगशिप मॉडल है। इसमें सबसे हाई-स्पेक 3.7kWh बैटरी लगाई गई है, जो 157 किलोमीटर की तक की रेंज देता है। इसके प्रो पैक मॉडल को अपडेट किया गया है। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस और टॉप-टियर फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इसे अभी भी केवल कोबाल्ट ब्लू और पेट्रल ऑरेंज कलर स्कीम में उपलब्ध है।

नए साल पर कावासाकी बाइक्स पर बंपर डिस्काउंट, निंजा 650 पर 45,000 रुपये की छूट

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी सुपरबाइक निर्माता कंपनी Kawasaki भारतीय ग्राहकों के लिए बंपर डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। जनवरी 2025 में कावासाकी 15000 रुपये से लेकर 45000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। कावासाकी अपनी Z900 Ninja 650 Versys 650 Ninja 300 और Ninja 500 बाइक पर छूट दे रही है। आइए जानते हैं कि Kawasaki अपनी इन बाइक्स पर कितना डिस्काउंट दे रही है।

नई दिल्ली। Kawasaki ने नए साल 2025 के अवसर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। इस डिस्काउंट ऑफर के तहत Z900, Ninja 650, Versys 650, Ninja 300 और Ninja 500 पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। ये ऑफर 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक या स्टॉक रहने तक रहने वाला है।

1. Kawasaki Ninja 300

कावासाकी के जिरिए पेश की जाने वाली निंजा 300 सबसे सस्ती स्पॉर्ट्स बाइक है। यह एक एंटी-लेवल स्पॉर्ट्स बाइक है, जिसपर कावासाकी काफी बेहतरीन ऑफर दे रही है।

कीमत और ऑफर: एक्स-शोरूम कीमत 3.43 रुपये पर इस बाइक पर 30,000 रुपये की छूट मिल रही है।

इंजन: इसमें 296 सीसी, लिक्विड-कूल्ड,



पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया है। पावर और टॉर्क: यह इंजन 11,000 RPM पर 38.8 bhp और 10,000 RPM पर 26.1 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

ट्रांसमिशन: छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी बेहतर बनाता है।

2. Kawasaki Ninja 500

कावासाकी निंजा 500 स्पॉर्ट्स बाइक को भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट के रूप में पेश किया जाता है। इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी बेहतरीन हैं।

कीमत और ऑफर: एक्स-शोरूम कीमत 5.24 लाख रुपये पर 15,000 रुपये की छूट मिल रही है।

इंजन: इसमें 451 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पावर और टॉर्क: यह इंजन 9,000 RPM पर

45 bhp और 6,000 RPM पर 42.6 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

ट्रांसमिशन: इसके इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

3. Kawasaki Ninja 650 कावासाकी निंजा 650 का डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी बेहतरीन हैं। यह बाइक उन लोगों को काफी पसंद आती है, जो ज्यादा पावर और लंबी दूरी की राइडिंग करना पसंद करते हैं।

कीमत और ऑफर: एक्स-शोरूम कीमत 7.16 लाख रुपये पर 45,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।

इंजन: इसमें 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पावर और टॉर्क: यह इंजन 8,000 RPM पर 67.3 bhp और 6,700 RPM पर 64 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

ट्रांसमिशन: इसके इंजन को मल्टी-डिस्क क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

4. Kawasaki Versys 650 कावासाकी वर्सेस 650 एक एडवेंचर टूर बाइक है। इस बाइक को शानदार डिजाइन, मजबूत स्ट्रक्चर और आरामदायक राइडिंग के लिए जाना जाता है।

कीमत और ऑफर: एक्स-शोरूम कीमत 7.77 लाख रुपये पर 30,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इंजन: इसमें 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है।

पावर और टॉर्क: यह इंजन 8,500 RPM पर 65.7 bhp और 7,000 RPM पर 61 Nm टॉर्क जोड़ा गया है।

ट्रांसमिशन: इसके इंजन को मल्टी-डिस्क क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

5. Kawasaki Z900 कावासाकी Z900 एक बेहतरीन और पावरफुल बाइक है, जो हाई स्पीड और पावर के साथ आती है। इसे स्पॉर्ट्स बाइक के लिए एक आइडल के लिए रूप में जाना जाता है।

कीमत और ऑफर: एक्स-शोरूम कीमत 9.29 लाख रुपये पर 40,000 रुपये की छूट दी जा रही है।

इंजन: इसमें 948 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इन्लाइन-फोर इंजन का इस्तेमाल किया गया है।

पावर, रेंज और तकनीकी फीचर्स कौन होगी बेहतर

परिवहन विशेष न्यूज

Hyundai Creta Electric और Maruti e Vitara दोनों ही भारत में 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होने वाली हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक के फीचर्स तो सामने आ गए हैं लेकिन ई-विटारा के फीचर्स का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि यह दोनों में से (Hyundai Creta Electric vs Maruti e Vitara) पावर रेंज और तकनीकी फीचर्स के मामले में कौन बेहतर रहने वाली है।

नई दिल्ली। Hyundai Creta Electric और Maruti e Vitara दोनों ही भारत में 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होगी। क्रेटा इलेक्ट्रिक के तकरीबन सभी फीचर्स का कंपनी की तरफ से खुलासा कर दिया गया है। बस इसकी कीमतों का खुलासा करना बाकी है। वहीं, अभी तक e Vitara किन फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च होगी इसके बारे में कंपनी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। भारतीय बाजार में यह दोनों ही एक-दूसरे से मुकाबला करते हुए दिखाई देती हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों के एक्सप्लेन्ड फीचर्स के बारे में बता रहे हैं।

1. **एक्सटिरियर्स (Exterior)**
Hyundai Creta Electric ऑटो-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और कनेक्टेड LED DRLs (ड्राइवर रीयलाइट्स): बेहतर रोशनी और आकर्षक लुक के लिए।
शाक-फिन एंटीना: आधुनिक और स्ट्राइलिश दिखने के लिए।
17-इंच एरो-स्टाइल एलॉय व्हील्स: एरोडायनेमिक डिजाइन और शानदार साइड व्यू के लिए।
एक्टिव एयर फ्लैस: बेहतर एरोडायनेमिक्स और कम हवा का प्रतिरोध करने के लिए।
Maruti e Vitara ऑटो-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और Y-शेड LED DRLs: स्पेशल और आकर्षक डिजाइन के लिए।
LED फॉग लाइट्स: खराब मौसम में बेहतर दृश्यता बनाए रखने के लिए।
अप टू 19-इंच व्हील्स (ग्लोबल-स्पेक AWD): ज्यादा बड़े व्हील्स और AWD (ऑल व्हील ड्राइव) ऑप्शन मिल सकता

2. **इंटीरियर्स (Interior)**
Hyundai Creta Electric इयूल-टोन व्हाइट और ब्लैक डैशबोर्ड: शानदार और प्रीमियम लुक के लिए।
लेडर सीट अपहोल्स्ट्री: आरामदायक और प्रीमियम सीटिंग के लिए।
एंबियंट लाइटिंग: इंटीरियर्स में एक अलग और आकर्षक माहौल बनाने के लिए।
Maruti e Vitara ऑटो-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और Y-शेड LED DRLs: कार की स्टाइल को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए।
दोनों ही कारों में शानदार और प्रीमियम इंटीरियर्स मिल सकते हैं, लेकिन क्रेटा इलेक्ट्रिक की इयूल-टोन डैशबोर्ड और एंबियंट लाइटिंग उसे थोड़ी और प्रीमियम बनाएगी।

3. **कंफर्ट और क्वीनियंस (Comfort and Convenience)**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

4. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

5. **सुरक्षा (Safety)**
Hyundai Creta Electric 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), EBD के साथ ABS, ESC: पैसेंजर की ज्यादा सेफ्टी के लिए।
ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स: बेहतर ब्रेकिंग और कंट्रोल के लिए।
360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS: पार्किंग और ड्राइविंग के दौरान अधिक सुरक्षा के लिए।
Maruti e Vitara 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), EBD के साथ ABS, ESC: पैसेंजर की ज्यादा सेफ्टी के लिए।
ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स: बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम कंट्रोल के लिए।
360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS: पार्किंग और ड्राइविंग के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

6. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

7. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।



किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

पैनोरमिक सनरूफ: खुला और ताजगी से भरपूर अनुभव के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: बिना तार के फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
दोनों गाड़ियों में समान कंफर्ट और क्वीनियंस फीचर्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन क्रेटा इलेक्ट्रिक में कुछ एक्सट्रा फीचर्स जैसे इयूल-जोन एसी और अधिक स्मार्ट डिस्प्ले मिलने वाला है, जिससे ड्राइविंग बेहतर हो सकती है।

8. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

9. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

10. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

11. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

12. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

13. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग, स्मार्ट और आरामदायक सफर के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: गर्मी में आरामदायक बैठने के लिए।
पैनोरमिक सनरूफ: कार के अंदर अधिक खुलापन और ताजगी के एहसास के लिए।
वायरलेस फोन चार्ज: आसानी से फोन चार्ज करने के लिए।
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs: बेहतर रिवर्स पार्किंग और रियर व्यू के लिए।
Maruti e Vitara 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: स्मार्ट और क्लियर डिस्प्ले के लिए।
ऑटो एसी विथ रियर वेंट्स: गर्मियों में भी आरामदायक और ठंडा माहौल बनाए रखने के लिए।
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स: फ्रंट सीट्स के लिए भी बेहतर वेंटिलेशन के दौरान ज्यादा सेफ्टी के लिए।

14. **पावर और रेंज**
Hyundai Creta Electric 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इयूल-जोन एसी विथ रियर वेंट्स: बेहतर ड्राइविंग

ग्लोबल एविएशन हब बनेगा भारत! नीति आयोग ने तैयार किया पूरा प्लान, बजट में बड़े एलान की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसमें एविएशन सेक्टर को कर छूट इस सेक्टर की कंपनियों को काम करने संबंधी नियमों को आसान बनाने और देश में विमान कंपनियों पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्कों में छूट देने के लिए एक समग्र पैकेज की घोषणा की जा सकती है।

नई दिल्ली। भारत का उड्डयन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में कई बार केंद्रीय उड्डयन मंत्रियों की तरफ से यह कहा भी जा चुका है कि वह भारत को एक वैश्विक एविएशन हब के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार पहली बार इस उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए एक समग्र नीति तैयार करने में जुटी है।

इसकी एक महत्वपूर्ण झलक अगले आम बजट में दिखेगी। माना रहा है कि आगामी बजट में एविएशन सेक्टर को कर छूट, इस सेक्टर की कंपनियों को काम करने संबंधी नियमों को आसान बनाने और देश में विमानन कंपनियों पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्कों में छूट देने के लिए एक समग्र पैकेज की घोषणा की जाएगी।

नीति आयोग ने तैयार किया है प्लान

पैकेज का प्रारूप नीति आयोग ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ गहन विमर्श के बाद तैयार



किया है। नीति आयोग का यह पैकेज कई चरणों में लागू होगा।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया, 'सरकार की भावी नीति पीएम नरेन्द्र मोदी की तरफ से सितंबर, 2024 में एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय बैठक में कही गई बात को मूल रूप देने वाला होगा। उसमें पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आम जनता तक हवाई यात्रा की सेवा को पहुंचाना, हवाई यात्रा को सुगम, किफायती और सभी के लिए उपलब्ध बनाने की होनी चाहिए।'

यह टियर-2 और टियर-3 श्रेणी के शहरों में निवेश बढ़ाने वाला और समूचे घरेलू उड्डयन सेक्टर में रोजगार के नए

अवसरों को बढ़ाने वाला होगा। बताते चलें कि नीति आयोग ने एविएशन सेक्टर को प्रोत्साहन देने की इस नीति के तहत विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव किया था और वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे रखा गया था, लेकिन राज्यों की सहमति नहीं मिल पाई।

हिसार को एविएशन हब बनाने पर लग सकती है मुहर

सरकार की भावी नीति में देश में दो एविएशन हब स्थापित करने की राह भी खुलेगी। पहले देश में एक एविएशन हब बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से उत्तर व

दक्षिण में एक-एक एविएशन बनाने की पेशकश की जाने वाली है। हाल ही में अमेरिकी सरकार की तरफ से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित हिसार एयरपोर्ट को एक एविएशन हब बनाने के लिए तकनीकी व वित्तीय मदद देने पर समझौता हुआ है।

हरियाणा की राज्य सरकार की तरफ से भी हिसार को एक वैश्विक एविएशन हब बनाने की बात कही गई है, लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

2047 तक देश में होंगे 400 एयरपोर्ट

रिटायरमेंट के लिए कैसे करें बचत, किन योजनाओं में लगाएं पैसा?

रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको सबसे पहले तय करना होगा कि रिटायर होने के बाद आपकी जरूरतें क्या होंगी और आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। साथ ही आप कितना बड़ा रिटायरमेंट फंड चाहते हैं। फिर आपको उसी हिसाब से बचत की शुरु करनी चाहिए। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से लेकर पीपीएफ और एनपीएस जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट के लिए आप जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू कर देंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। अधिकतर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह है कि आपको हर साल में 30 साल की उम्र से अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आप बड़ा रिटायरमेंट फंड बना पाएंगे और आपकी बुढ़ापे में आर्थिक नजरिये से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें?

आपको सबसे पहले तय करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जरूरतें क्या होंगी और आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। साथ ही, आप कितना बड़ा रिटायरमेंट फंड चाहते हैं। फिर आपको उसी हिसाब से बचत की शुरु करनी चाहिए। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से लेकर पीपीएफ और एनपीएस जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की कुल संख्या 22 करोड़ के पार कर जाने की संभावना है। यह संख्या वर्ष 2030 तक 40 करोड़ हो जाने और भारतीय विमानन कंपनियों के पास विमानों की मौजूदा संख्या

Retirement के लिए बचत कैसे करें?

गैर-जरूरी खर्च कम करें और बचत करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, तो उसे भी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। एकमुश्त पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी सेविंग से बड़ा फंड तैयार करें।

रिटायरमेंट लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश को नियमित रूप से समीक्षा करत रहें।

मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर करें निवेश

मुद्रास्फीति (inflation) का मतलब है कि चीजों के दाम सालाना आधार पर किस तरह से बढ़ रहे हैं। भारत में अभी मुद्रास्फीति 5 फीसदी के करीब है। लेकिन, यह 1974 में 28 फीसदी के पार पहुंच गई थी। इसलिए आपको उन योजनाओं में निवेश करना चाहिए, जहां अधिक रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहे। लंबी अवधि में मुद्रास्फीति आपकी आर्थिक स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको इस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए।

रिस्क मैनेजमेंट का भी रखें ख्याल

रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय रिस्क मैनेजमेंट (Risk Management) का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी पूरी बचत किसी एक ही स्कीम में निवेश न करें। उसे अलग-अलग निवेश माध्यमों में लगाएं। जैसे कि कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाएं और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक खरीदें।

वर्ष 2047 तक भारत में 400 एयरपोर्ट होंगे। सिर्फ एयरपोर्ट निर्माण के लिए 24 अरब डॉलर के निवेश की दरकार है। जबकि विमानन कंपनियों को नये विमान खरीदने के लिए 150 अरब डॉलर के वित्त

बैंक नीलामी में अब आसानी से खरीद सकेंगे फ्लैट-जमीन और गाड़ी, सरकार ने दी ये खास सुविधा

वित्त मंत्रालय ने ई-ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट लॉन्च किया है। अभी मकान फ्लैट व वाहन की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल पर जाकर लोग उसे सर्च करते हैं। अब बैंकनेट पोर्टल पर भी इस प्रकार के सर्च कर खरीदारी की जा सकती है। अभी ही बैंकनेट पोर्टल पर देश के विभिन्न स्थानों पर नीलामी के 122500 प्रॉपर्टी की विस्तृत जानकारी अपलोड हो चुकी है।

नई दिल्ली। अब बैंक की तरफ से होने वाली नीलामी में फ्लैट से लेकर आवासीय व कृषि जमीन के साथ प्लांट व मशीनरी की आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। नीलामी प्रक्रिया को आसान एवं सभी के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम.नागाराजु ने बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया।

इस पोर्टल पर सभी सरकारी बैंक फ्लैट, मकान, जमीन, वाहन, मशीनरी, प्लांट की पूरी जानकारी देंगे। पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति नीलामी होने वाली सभी प्रॉपर्टी की जानकारी लेकर उसमें भाग ले सकता है। अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही



बैंक नीलामी में चीजें खरीदना होगा आसान

है तो काल सेंटर को काल भी कर सकता है।

अभी अलग-अलग पोर्टल पर करना पड़ता है सर्च

अभी मकान, फ्लैट व वाहन की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के पोर्टल पर जाकर लोग उसे सर्च करते हैं। अब बैंकनेट पोर्टल पर भी इस प्रकार के सर्च कर खरीदारी की जा सकती है। अभी ही बैंकनेट पोर्टल पर देश के विभिन्न स्थानों पर नीलामी के 1,22,500 प्रॉपर्टी की विस्तृत जानकारी अपलोड हो चुकी है। पोर्टल पर प्रॉपर्टी की नीलामी से पहले व नीलामी के साथ नीलामी के बाद की पूरी जानकारी दी जाएगी।

सरकारी बैंक लोन में डिफॉल्ट होने वाले की प्रॉपर्टी, जमीन, प्लांट, मशीनरी, वाहनों की नीलामी पर अपनी रकम वसूलती है। इस काम के लिए बैंक अखबारों में इशतिहार देकर लोगों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं।

बैंकनेट पर सभी सरकारी बैंक नीलामी की जानकारी देंगे। इस पोर्टल के लॉन्च होने से बैंक को इस नीलामी में अधिक से अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे और उन्हें अधिक कीमत मिल सकती है। इस पोर्टल पर जाकर खरीदारी करने पर ग्राहकों के साथ किसी धोखाधड़ी की कोई आशंका नहीं रहेगी।

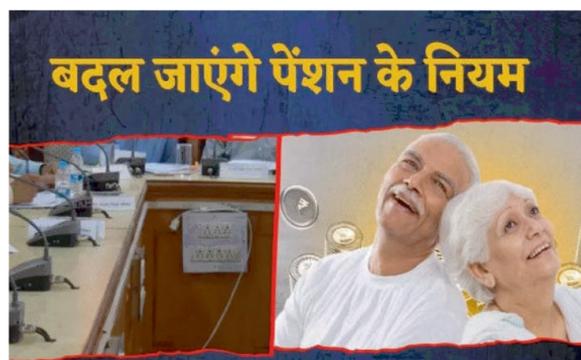
पेंशनधारकों को सरकार का बड़ा तोहफा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू; पढ़ें क्या होगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफओ पेंशन की नई प्रणाली के कामयाब होने की घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पूर्ण कार्यान्वयन एक मील का पत्थर है। ईपीएफओ की यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक और शाखा से अपनी पेंशन हासिल करने में सक्षम बनाता है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन सेवाओं के तहत केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शत-प्रतिशत कामयाबी के साथ पूरे देश में लागू हो गई है। पेंशन भुगतान सेवाओं की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को एक साथ पेंशन का खाते में भुगतान कर दिया है।

यह कदम एक मील का पत्थर: मनसुख मंडाविया
इसमें पेंशन धारकों को 1570 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की गई है।



बदल जाएंगे पेंशन के नियम

ईपीएफओ पेंशन की नई प्रणाली के कामयाब होने की घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पूर्ण कार्यान्वयन एक मील का पत्थर है।

ईपीएफओ की यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक और शाखा से अपनी पेंशन हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसमें भौतिक स्थापन के लिए पेंशनभोगियों के आने-जाने की आवश्यकता नहीं और पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल है।

पेंशन भुगतान की नई प्रणाली से हम तय कर रहे नया मानदंड

मंडाविया ने कहा कि ईपीएफओ सेवाओं को आधुनिक बनाने और पेंशनभोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक और शाखा से अपनी पेंशन हासिल करने में इसके जरिए हम नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं।

मालूम हो कि सीपीपीएस का पहला पायलट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू

और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसमें 49,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये पेंशन का भुगतान किया गया।

किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे पेंशनभोगी

दूसरा पायलट नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू हुआ जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 213 करोड़ रुपये पेंशन वितरित हुए। सीपीपीएस के तहत ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। इसमें पेंशनभोगी किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेगा बल्कि पेंशन शुरू होने के समय किसी भी स्थापन के लिए उसे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होते ही तुरंत जमा हो जाएगी।

जनवरी 2025 से सीपीपीएस पूरे देश में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल लें। रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाने वाले पेंशनभोगियों को इससे बड़ी सहूलियत होगी।

क्या चीनी का बढ़ेगा भाव? मौजूदा मार्केटिंग सीजन में 16 फीसदी घटा प्रोडक्शन

2024-25 सीजन के पहली तिमाही में चीनी का उत्पादन 95.40 लाख टन रहा। यह आंकड़ा एक साल पहले 113.01 लाख टन था। इस साल 493 चीनी मिलों में पेराई हो रही थी जबकि पिछले 512 चीनी मिल चालू थीं। उत्पादन के आंकड़ों एथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल को शामिल नहीं किया गया है। अगर चीनी उत्पादन आगे भी कम रहा तो इसके भाव बढ़ सकते हैं।

नई दिल्ली। चीनी का उत्पादन मौजूदा मार्केटिंग सीजन की पहली तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले करीब 16 फीसदी घटा है। इससे चीनी के भाव में उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने चीनी के उत्पादन का पहला अनुमान जारी कर दिया है। चीनी का मार्केटिंग सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होता है।

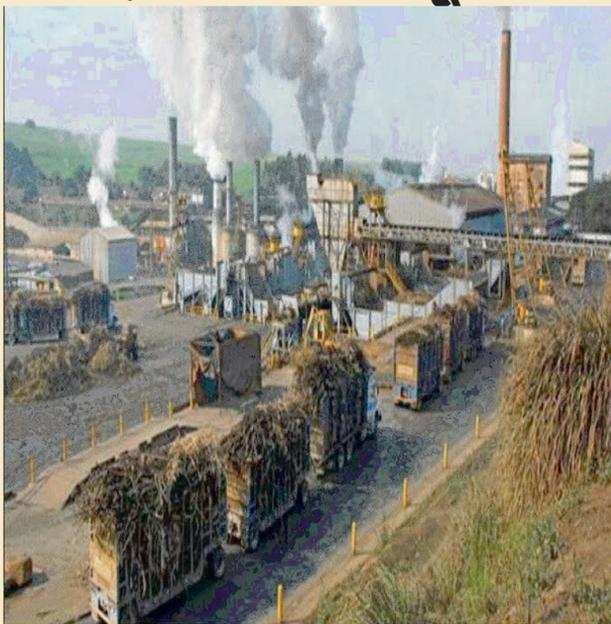
शुगर प्रोडक्शन कितना रहा?

2024-25 सीजन के पहली तिमाही में चीनी का उत्पादन 95.40 लाख टन रहा। यह आंकड़ा एक साल पहले 113.01 लाख टन था। इस साल 493 चीनी मिलों में पेराई हो रही थी, जबकि पिछले 512 चीनी मिल चालू थीं। उत्पादन के आंकड़ों एथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल को शामिल नहीं किया गया है।

चीनी उत्पादन घटने की वजह

ISMA के मुताबिक, कुछ राज्यों में एथेनॉल डायवर्जन बढ़ा है। इस वजह से चीनी उत्पादन में गिरावट आई है। एथेनॉल के लिए साल 2023-24 डायवर्जन 21.50 लाख टन रहा है जबकि 2024-25 में एथेनॉल के लिए 40 लाख टन चीनी का डायवर्जन रहा। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में पेराई देर से शुरू हुई। यह भी उत्पादन घटने की एक बड़ी वजह है।

क्या चीनी के बढ़ेंगे दाम?



चीनी उद्योग के जानकारों का कहना है कि अभी कई मिलों में पेराई चल रही है। इससे उम्मीद है कि चीनी का उत्पादन बढ़ जाएगा। हालांकि, अगर उत्पादन ज्यादा कम रहा, तो उसका असर चीनी की कीमतों पर भी दिख सकता है। चीनी मंडी के मुताबिक, दिल्ली में चीनी का मौजूदा खुदरा भाव 42 रुपये किलो है।

क्या चीनी की कमी हो सकती है?

ISMA के डायरेक्टर दीपक बल्लानी के मुताबिक, देश में चीनी की किल्लत होने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी की कोई कमी नहीं है। अगले साल के लिए चीनी का प्रोडक्शन अच्छा लग रहा है।

बल्लानी ने कहा, 'महाराष्ट्र और कर्नाटक में पेराई देर से शुरू हुई है। पिछले 15 दिनों का क्रॉसिंग रेट पिछले साल से अच्छा है। इससे चीनी उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना है।'

10 लाख टन एक्सपोर्ट की मांगी मंजूरी

बल्लानी ने यह भी कहा कि चीनी मिलों ने सरकार से 10 लाख टन के एक्सपोर्ट की मंजूरी मांगी है। अगर सरकार ने इजाजत दे दी, तो इससे मिलों को आर्थिक तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से चीनी की मिनिमम सेलिंग प्राइस भी बढ़ाने की मांग की है। सरकार एथेनॉल का भाव बढ़ाने पर भी जल्द फैसला ले सकती है।

बेसिक होम लोन का रेफरल एजेंट नेटवर्क को बढ़ाने का प्लान; 50 हजार लोगों को मिलेगा कमाई का मौका

बेसिक होम लोन की कामयाबी में रेफरल एजेंट नेटवर्क का बड़ा हाथ है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट हाउसवाइफ या आम आदमी कंपनी के लिए ग्राहक लाकर कमाई कर सकता है। कंपनी के रेफरल एजेंट नेटवर्क से फिलहाल 15000 लोग जुड़े हैं। कंपनी इसे अगले 12 महीने में बढ़ाकर 50000 तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

नई दिल्ली। दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचौलिया के निवेश वाली बेसिक होम लोन की तेज ग्रोथ कर रही है। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ग्रोथ हासिल की है। इसने अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है। कंपनी अपने रेफरल एजेंट नेटवर्क में बड़ा विस्तार कर रही है। इससे बहुत-से पार्ट-टाइम राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार कमाई का मौका मिल सकता है। बेसिक होम लोन के को-फाउंडर और सीईओ अतुल मोंगा ने दिल्ली और मुंबई में आयोजित सालाना कार्यक्रम 'हडल' के दौरान कहा कि कंपनी 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए सभी के लिए घर खरीदने के सपने को साकार करने का प्रयास कर रही है।

रेफरल एजेंट नेटवर्क का विस्तार करने की योजना

बेसिक होम लोन की कामयाबी में रेफरल एजेंट नेटवर्क का बड़ा हाथ है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट, हाउसवाइफ या आम आदमी कंपनी के लिए ग्राहक लाकर कमाई कर सकता है। इस रेफरल एजेंट नेटवर्क में प्रॉपर्टी डीलर्स,



चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। यह न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि संभावित ग्राहकों के लिए होम लोन हासिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाती है। कंपनी के रेफरल एजेंट नेटवर्क से फिलहाल 15,000 लोग जुड़े हैं। कंपनी इसे अगले 12 महीने में बढ़ाकर 50,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके सीईओ अतुल मोंगा ने कहा, रहमारे एजेंट और साझेदार हमारी सफलता की नींव हैं। हडल 2024 यह साबित करता है कि मार्गेज इंडस्ट्री में नवाचार और समावेशन के प्रति हमारा समर्पण अडिग है।

आधुनिक उपकरण और बेहतर अवसर

बेसिक होम लोन अपने एजेंट्स को आधुनिक उपकरण, परफॉर्मेंस इंसेंटिव और विकास के अवसर प्रदान करता है। कंपनी का लक्ष्य है कि यह नेटवर्क न केवल बड़े शहरों में बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी अधिक प्रभावशाली बने। इससे नए ग्रेजुएट्स और पेशेवरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

2020 में स्थापित बेसिक होम लोन का उद्देश्य भारत में 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को पूरा करना है। यह देशभर में 650 जिलों में काम कर रहा है और हर महीने \$1 बिलियन से अधिक के लोन आवेदन प्रोसेस करता है।

बेसिक होम लोन के निवेशकों में बड़े नाम बेसिक होम लोन के इन्वेस्टर की लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। इनमें शेयर मार्केट के मशहूर निवेशक आशीष कचौलिया भी शामिल हैं। अगर अन्य बड़े निवेशकों की बात करें, तो इसमें बटलसमैन इंडिया इन्वेस्टमेंट, सीई-वेंचर्स, निखिल कामथ गृहास, पिकास कैपिटल, वेंचर कैपिटल, 9 यूनिफॉर्स, अल्सफील्ड कैपिटल, गुड कैपिटल, डेक्सटर एंजल्स, आईआईएम इंदौर एल्यूमीनार्ड एंजल फंड, कॉम्पक्रैडिबल वेंचर फंड आदि का सपोर्ट हासिल है।

रिश्ते सुधरने से पहले आई दरार, भारत की दो टूक: लद्दाख में चीन का गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं

भारत और चीन के बीच हाल ही में रिश्ते सुधरने को लेकर समझौता बनी थी लेकिन अब इन कोशिशों में दरार आती दिख रही है। चीन के होना प्रान्त में दो नये राज्य बनाने की घोषणा का भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने क्षेत्र को लद्दाख का हिस्सा बताया है और कहा है कि इस पर चीन का गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति श्री चिन्मयिणी के बीच अक्टूबर, 2024 में ही हुई मुलाकात में भारत व चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की सहमति बनी और तीन महीने भी नहीं हुए इस सहमति के दरकरने के संकेत मिलने लगे हैं।

पहले चीन की तरफ से अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के निगम स्थल पर 137 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल बांध बनाने की घोषणा की और फिर भारत के क्षेत्र लद्दाख से जुड़े पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाये होतान प्रान्त में दो नये राज्य बनाने की घोषणा कर दी।

भारत ने कहा- गैरकानूनी कब्जा भारत ने इन दोनों घोषणाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कह दिया है कि लद्दाख के किसी हिस्से पर चीन का गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं है। वैसे इस जमीन पर चीन का कब्जा तकरीबन छह दशकों से है। इसके साथ ही सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना के लिए बांध बनाने की योजना को लेकर भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अधिकार है।



अक्टूबर में भारत चीन के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात, उसके बाद विदेश मंत्रियों और सीमा विवाद सुलझाने के लिए गठित विशेष प्रतिनिधियों के बीच की बैठक से यह संकेत मिले थे कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। अब देखना होगा कि चीन की तरफ से उकसावे भरे कदम उठाने के बाद भारत इस पर सिर्फ प्रतिक्रिया जता कर ही रह जाता है या इस बारे में अपनी कोई स्पष्ट रणनीति भी बनाता है।

चीन का कदम उकसावे वाला हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन की तरफ से उठाये जाने वाला कदम उकसावे वाला था और भारत ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी है।

इसका रिश्तों पर सुधारने को लेकर उठाये जाने वाले कदमों पर शायद ही कोई असर हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने चीन की पनबिजली परियोजना की घोषणा को लेकर कहा, 'हमने चीन की समाचार एजेंसी में एक रिपोर्ट देखी है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्थित यार्लुंग त्सांगपो नदी पर एक पनबिजली परियोजना लागू की जा रही है। इस नदी के तट पर स्थित देश होने की वजह से भारत का भी इस पर अधिकार है और कई स्तरों पर इस मुद्दे को चीन के समक्ष उठाया है।'

उन्होंने कहा, 'हमने विशेषज्ञ दलों के माध्यम से और राजनयिक स्तर पर भी अपनी चिंताओं को लगातार व्यक्त किया है। अब जो

नई रिपोर्ट आई है, उसके बाद इस बारे में डाउनस्ट्रीम के देशों के साथ ज्यादा पारदर्शिता व विमर्श की जरूरत है। चीन से यह आग्रह किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी गतिविधियों से डाउनस्ट्रीम देशों (भारत, बांग्लादेश) के हित प्रभावित नहीं हो। हम इस पर लगातार नजर बना कर रखेंगे और अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह उपाय करेंगे।'

भारत ने बताया लद्दाख का हिस्सा जायसवाल ने जब चीन की तरफ से अक्साई चीन इलाके (इस पर भारत का लद्दाख का हिस्सा होने का ऐतिहासिक दावा) में दो नये प्रान्त बनाने के फैसले के बारे में पूछा गया तो

उनका जवाब था कि जिस होतान (चीन की तरफ से दिया गया नाम) प्रान्त में दो नये प्रान्त बनाने का फैसला किया गया है, वह तथाकथित हिस्सा भारत के लद्दाख का हिस्सा है। हमने इस क्षेत्र में चीन के किसी भी गैरकानूनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दो नये प्रान्त बनाने के फैसले से भारत के पारंपरिक रूख पर कोई असर नहीं होगा। यह भारत के संप्रभु क्षेत्र पर चीन की तरफ से गैरकानूनी व जबरदस्ती से किया गया कब्जा है। हमने राजनयिक तरीके से अपनी गंभीर प्रतिक्रिया जता दी है। सनद रहे कि चीन ने अक्साई चीन के करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है।

आखिर क्यों नहीं थम रहा रुपये में गिरावट का सिलसिला

निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यहास को बढ़ाता है। भारतीय रुपये में गिरावट बाहरी क्षेत्र की कमजोरियों के बीच मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पूंजी बहिर्वाह के साथ-साथ राजकोषीय घाटे जैसे घरेलू कारकों से उत्पन्न होते हैं। भारत के बाहरी लचीलेपन को बढ़ाने और इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय महत्वपूर्ण हैं।

- डॉ सत्यवान सौरभ

सितंबर 2024 के शेयर शिखर के बाद निरंतर बहिर्वाह ने रुपये को कमजोर कर दिया क्योंकि निवेशक अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की अटकलों के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर चले गए। उच्च व्यापार घाटे जैसे व्यापार घाटे आयात पर बाहरी निरभरता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा के लिए, रुपये की कमजोरी के दौरान चालू खाता घाटा बढ़ाते हैं। रुपये के अवमूल्यन के साथ भारत का कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ गया, जिससे 2024 का व्यापार घाटा बढ़कर \$75 बिलियन के करीब पहुँच गया।

टैरिफ की धमकियाँ और ब्रिक्स मुद्रा विवाद जैसे वैश्विक घटनाएँ भारत के बाहरी व्यापार और निवेश के लिए अनिश्चितताएँ पैदा करके अस्थिरता को

बढ़ाती हैं। ब्रिक्स देशों की मुद्रा योजनाओं के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की 2024 टैरिफ चेतावनी ने बाजार में बिकवाली को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की बाहरी स्थिरता कमजोर हुई। रुपये को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी निरभरता निरंतर वैश्विक बाजार अशांति के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक लचीलेपन को प्रतिबंधित करती है।

रुपये को वापस 85.53 पर लाने के लिए दिसम्बर 2024 में एक ही तिमाही में \$20 बिलियन से अधिक के भंडार को समाप्त कर दिया। कमजोर रुपया घरेलू मौद्रिक नीतियों को प्रतिबंधित करता है, महंगे आयातों के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाता है जबकि विकास सम्बंधी चिंताओं को दूर करने के लिए राजकोषीय स्थान को कम करता है। दिसम्बर 2024 में कच्चे तेल के आयात की लागत 15% बढ़ गई, जिससे नीति निर्माताओं पर मुद्रा प्रबंधन और राजकोषीय विस्तार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने का दबाव पड़ा।

टैरिफ या प्रतिबंध जैसे संरक्षणवादी व्यापार उपाय, व्यापार संतुलन को बाधित करके मुद्रा स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष अस्थिरता पैदा करते हैं, जिससे सुरक्षित-पनाहगाह डॉलर की मांग बढ़ती है और उभरते बाजारों की मुद्राएँ कमजोर होती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे भारत के आयात बिल पर दबाव पड़ा और रुपये का मूल्य कम हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण भारत से पूंजी का बहिर्वाह होता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।

2022-23 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी के कारण विदेशी



पोर्टफोलियो का बहिर्वाह हुआ, जिससे रुपया कमजोर हुआ।

निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ने से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कच्चे तेल और सोने के बढ़ते आयात के कारण 2022 में भारत का रिकॉर्ड व्यापार घाटा रुपये के मूल्यहास को बढ़ाता है। उच्च घरेलू मुद्रास्फीति मुद्रा मूल्य को कम करती है, जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। कच्चे तेल जैसे अलोचदार आयातों की बढ़ती कीमतों ने भारत के आयात बिलों को बढ़ा दिया, जिससे 2023 में रुपया कमजोर हो गया। घरेलू और विदेशी निवेश में गिरावट कमजोर आर्थिक विकास का संकेत देती है, जिससे मुद्रा प्रवाह हतोत्साहित होता है। 2024 में, कॉर्पोरेट प्रदर्शन में कमी और स्टॉक वैल्यूएशन में वृद्धि के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह हुआ। मुद्रा को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा सीमित हैं और केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं। दिसम्बर 2024 में आरबीआई के देर से हस्तक्षेप ने रुपये को अस्थायी रूप से 85.53 प्रति डॉलर पर

स्थिर करने में कामयाबी हासिल की। राजकोषीय रूप से विश्व सरकार बाहरी झटकों को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता को कम करती है, जिससे मुद्रा स्थिरता में विश्वास कमजोर होता है। महामारी के दौरान भारत के रिकॉर्ड राजकोषीय घाटे ने बाहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपायों को सीमित कर दिया। मुद्रा नीतियों पर सरकार का स्पष्ट रुख निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और सट्टा दबाव कम करता है। आरबीआई गवर्नर द्वारा 2024 में डी-डॉलर इजेशन को खारिज करने से बाजार आश्वस्त हुआ, जिससे रुपये के मूल्यहास की चिंताएँ अस्थायी रूप से कम हो गईं।

बाह्य लचीलेपन को मजबूत करने के उपाय हैं, निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए मूल्यवर्धित विनिर्माण और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने से व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। विविध आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौते करके अस्थिर कच्चे

तेल और आवश्यक आयात पर निर्भरता कम करें। रूस और मध्य पूर्वी देशों से कच्चे तेल के आयात का विस्तार करने से 2023 में औसत तेल आयात लागत कम हो गई। प्रभावी मुद्रा स्थिरीकरण के लिए सॉवरेन वेलथ फंड और सोने के संचय के माध्यम से मजबूत भंडार बनाएँ।

रिजर्व बैंक के अनुसार 2021 में \$600 बिलियन के रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार ने महामारी के दौरान अस्थिरता को प्रबंधित करने में मदद की। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को निपटाने, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और विनिर्माण दर जोखिमों को कम करने के लिए समझौते में शामिल हों। भारत-रूस रुपया-रुबल व्यापार तंत्र ने रूस-यूक्रेन संकट के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया। मुद्रा जोखिमों से बचने के लिए अल्पकालिक बाहरी ऋण को कम करते हुए कम लागत और लंबी अवधि के उधार को प्राथमिकता दें।

भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने में वृद्धि ने 2023 में पुनर्भुगतान अस्थिरता को कम करने के साथ स्थिर विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक लचीलेपन के लिए एक मजबूत बाहरी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति सुनिश्चित करके, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर और रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर, भारत मुद्रा अस्थिरता को कम कर सकता है। संरचनात्मक सुधारों और वैश्विक आर्थिक एकीकरण पर जोर देने वाली एक दूरदर्शी रणनीति दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

चार दिन की जिंदगी

जीवन क्या है रास्तों पर भटकता राही, यहाँ सराय में ठहरा मुसाफिर चार दिन की जिंदगी, चार कंधों पर चूँ ही चले जाना है।

कोई कभी भी किसी के लिए नहीं रुका, यह बहता हुआ पानी अविरोध बहता रहता है सुख-दुःख उतार-चढ़ाव सहता रहता है, पर सब भूल जाता है कि चार दिन की जिंदगी है।

लाख अंधेरों में रहने बाले तू दर मत, एक उम्मीद की किरण से प्रकाश प्रफुल्लित होगा उजियारों से जीवन आगे बढ़ेगा, चार दिन की जिंदगी चार कंधों पर चूँ ही चले जाना है।

क्रोध, माया, लोभ, धमंड के साथ तू मत उलझ, यह सब मिथ्या है यही रह जाएगा तेरे मीठे बोल दुनिया याद रखेगी, चार दिन की जिंदगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा।

आज भागता फिर रहा तू ईसान अपने मूल फर्ज़ को भुलाए, संसार के बंधनों में बंध भटकता है। एक दिन राख हो जाएगा, चार दिन की जिंदगी है चार कंधों पर चूँ ही चले जाना है ॥ हरिहर सिंह चौहान



मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: 500 ट्रेफिक कर्मचारियों की होगी नियुक्ति



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओइशिया

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोअर पीएमजी से राम मंदिर तक जागरूकता पदयात्रा शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने ओइशिया यात्री ऐप भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के अनुपालन के बारे में

जागरूकता बढ़ाई है। यातायात समस्याओं के समाधान के लिए 2,000 यातायात कर्मचारियों के पद सृजित किये जायेंगे। इस वर्ष 500 यातायात अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का संदेश सुरक्षित घर लौटने का है। यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश दिया गया है।



अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन दिनांक 3 जनवरी 2025 को करवाया गया है जिसमें पदाधिकारी सहित दो सलाहकार के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ। काफी दिनों के बाद यह संस्था रजिस्ट्रेशन हुई है अब इसका खाता बैंक में खुलवाकर समाज के विकास कार्य किया जाएगा व जरूरत होगी उसे हिसाब से मेबरशिप बनवाकर संस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। तेलंगाना के सभी बड़ेरो अध्यक्ष और सचिवो से मिलकर एक मीटिंग रखी जाएगी। समाज के विकास कार्य में आप सबका सहयोग जरूरी है। माह सभा अध्यक्ष हरजीराम काग, महासभा सचिव सोहनलाल हाम्बड़ बाकी अन्य पदाधिकारी हुकमराम सेपटा माणकचन्द गेहलोत, गीरधालाल काग, प्रभुराम हांबड़, CA जसराज बर्वा राजुराम परिहार, सुरेश, शमशाबाद बडेर अध्यक्ष आशाराम गेहलोत, कोरेमुला बडेर अध्यक्ष कालुराम काग, मनि कोण्डा बडेर अध्यक्ष बाबूलाल भायल, व समाज बन्धु उपस्थिती में रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह सूचना अध्यक्ष अखिल भारतीय सीरवी महासभा तेलंगाना के हरजीराम काग के द्वारा दी गई।

पत्र लेखन कला में म प्र का डंका बजाते कलमकार

स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

'बौते वर्ष 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक देश विदेश के तमाम प्रमुख अखबारों में विभिन्न विषयों पर अपनी कलम से पत्र संपादक के नाम के लिए पत्र लेखकों के मध्य प्रदेश के अनमोल रत्नों में वरिष्ठ पत्र लेखक श्री संजय वर्मा दृष्टि मनावर के कुल 2172 पत्र और लेख कविता प्रकाशित हुए। दुसरे रत्न में वरिष्ठ पत्र लेखक हम सभी के मार्गदर्शक श्री अमृतलाल मारू इन्दौर जिनकी लेखनी से 2024 में पूरे साल में देश विदेशों के अखबारों में 1372 पत्र प्रकाशित हुए। यह दोनों पत्र लेखक हमारी धरोहर यानी लेखनी के श्री गणेश को बचायें हुए हैं। अस्सी के दशक में पत्र लेखकों को जो मान सम्मान प्राप्त था उसी पीढ़ी के यह लेखकद्वय पत्र लेखन के मध्यम में विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। दोनों की लेखन कला इस बात का भी प्रमाण है कि निरंतर लेखन के जरिए समाजसामयिक और सामाजिक मुद्दों को सहेज और सरल भाषा में प्रस्तुत कर उसे जन आकर्षक का केंद्र बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जमाने में लेखक द्वय जिस तरह लेखन कला को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं वह अपने आप में अद्वितीय है। पत्र लेखन कला का जीवित रहना साहित्य की अमरता के लिए भी वरदान है। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास लेखक कुनबे को दीर्घायु बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आप दोनों कलमकार को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ। मध्य प्रदेश के इन दो पत्र लेखकों ने पूरे देश में सम्मान प्राप्त किया। ऐसे तो पत्र लेखक कला को मध्य प्रदेश की कलम ने ही संभाल कर रखा है पूरे देश में उन्हीं सभी लेखकों की लेखनी अपनी बात कह रही है यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।

